



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]
No. 148]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 2003/ज्येष्ठ 27, 1925
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 2003/JYAISTHA 27, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 जून, 2003

विषय :—इंडोनेशिया तथा यूरोपीय संघ के मूल के या वहाँ से निर्यातित 80 जीएसएम तथा इससे अधिक के पेपर तथा पेपरबोर्ड सहित कोटेड पेपर के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच शुरू करना।

सं० 14/7/2003-डीजीएडी.—मैसर्स बिल्ट ग्राफिक्स पेपर्स लिमिटेड गुड़गाँव, हरियाणा ने सीमाशुल्क टैरिफ(संशोधन) अधिनियम 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसे इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ के मूल के या वहाँ से निर्यातित कोटेड पेपर के पाटन का आरोप लगाया है तथा पाटनरोधी जाँच शुरू करने एवं पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

- वर्तमान याचिका में जाँचाधीन उत्पाद कोटेड पेपर है जिसमें 80 जीएसएम तथा इससे अधिक के पेपर तथा पेपरबोर्ड जिन्हें इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है शामिल हैं। इस

उत्पाद का उपयोग उच्च गुणवत्ता के मुद्रण कार्य, जिनमें विविध पत्रिकाएँ, प्रचार सामग्री, कैलेंडर, पोस्टर, पुस्तकें इत्यादि शामिल हैं के लिए किया जाता है। यह उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के सीमाशुल्क शीर्ष 4810 के तहत वर्गीकृत है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा वर्तमान जाँच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग की स्थिति

3. यह याचिका मैसर्स बिल्ट ग्राफिक्स पेपर्स लिमिटेड गुड़गाँव, हरियाणा द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र प्रमुख उत्पादक है। प्राधिकारी ने पाया है कि भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा 95% बनता है। मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि०, यमुनानगर तथा मैसर्स बिल्ट इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कंपनी लि० कोयम्बटूर जिनका हिस्सा घरेलू उत्पादन में क्रमशः 1.94% तथा 2.11% बनता है, ने याचिका का समर्थन किया है अतः याचिकाकर्ता तथा याचिका का समर्थन करने वाली उक्त अन्य कंपनियाँ उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3)(क) के अनुसार याचिका दायर करने के लिए घरेलू उद्योग की स्थिति को पूरा करती हैं।

शामिल देश

4. वर्तमान जाँच में शामिल देश इंडोनेशिया तथा यूरोपीय संघ हैं (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है)।

समान वस्तु

5. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों तथा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई अन्तर नहीं है। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपर्युक्त नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है

सामान्य मूल्य

6. याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा कच्ची सामग्री की अंतरराष्ट्रीय कीमत तथा भारतीय उद्योग के खपत मानकों के अनुसार परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर किया है। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य पर परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर विचार किया है।

निर्यात कीमत

7. याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण गौण स्रोतों से एकत्र किए गए आयात संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किया है। कारखाना द्वारा निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा निर्यातक देश में पत्तन व्ययों, पत्तन हैंडलिंग तथा पत्तन प्रभारों के लिए समायोजनों को दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

8. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

9. याचिकाकर्ता ने वास्तविक क्षति तथा क्षति के खतरे से संबंधित विभिन्न मापदंडों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि दर, कुल मांग के अनुपात में बाजार हिस्से में वृद्धि, भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में कमी, बिक्री मूल्य तथा इकाई कीमत में गिरावट, निवेश पर कम आय, कीमत कटौती तथा कीमत ह्रास जैसे मापदंडों जैसे प्रथम दृष्टया सामूहिक तथा संचयी रूप से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है तथा इसे क्षति होने का खतरा भी बना हुआ है।

पाटनरोधी जाँच शुरू करना

10. पूर्ववर्ती पैराग्राफों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के अरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और उसके प्रभाव की पाटनरोधी जाँच शुरू करते हैं।

जाँच की अवधि

11. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 जनवरी 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक की है।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में इस अधिसूचना से संबंधित ज्ञात आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तथा

निर्धारित देश से निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज दें।

उपरोक्त नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों, जो पाटन, क्षति और कारणात्मकता के संबंध में जाँच के लिए संगत सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, को भी अवसर प्रदान करते हैं। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

समय सीमा

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्याताकों और आयाताकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। यह नोट किया जाए कि अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त समयावधि को बढ़ाए जाने के बारे में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

14. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी सूचना जुटाने से माना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा महत्वपूर्ण ढंग से जांच से बाधा डालती है अथवा सूचना किसी भी रूप में अधूरी होती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2003

Subject : Initiation of anti-dumping investigations concerning import of Coated paper including paper and paperboard of 80 GSM and above originating in or exported from Indonesia and European Union.

No. 14/7/2003-DGAD.— M/s BILT Graphics Papers Ltd, Gurgaon, Haryana has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Coated paper originating in or exported from Indonesia and European Union and have requested for Anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

2. The product under investigation in the present petition is Coated paper including paper and paperboard of 80 GSM and above (hereinafter referred to as subject goods). This product is used for high quality printing jobs including various magazines, publicity material, calendars, posters, books etc. This product is classified under Customs Heading 4810 of the first schedule of the Customs tariff act, 1975. Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

DOMESTIC INDUSTRY STANDING

3. The petition has been filed by M/s BILT Graphics Paper Ltd, Gurgaon, Haryana. The petitioner has claimed that they are the only major producer of subject goods in India. The Authority observes that the petitioner accounts for 95% of the domestic production for the subject goods in India. M/s Ballarpur Industries Ltd, Yamunanagar and M/s BILT Industrial Packaging company Ltd, Coimbatore who account for 1.94% and 2.11% of the domestic production respectively, have supported the petitioner. Therefore, the petitioner and the other said companies supporting the petition satisfy the criteria of standing as

domestic industry to file the petition in terms of Rule 5(3)(a) of the Rules supra.

COUNTRIES INVOLVED

4. The countries involved in the present investigation are Indonesia and European Union (hereinafter referred to as subject countries).

LIKE ARTICLE

5. The petitioner has claimed that there is no difference between the products manufactured by them and the subject goods imported from the subject countries. Therefore, for the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles of the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules, supra.

NORMAL VALUE

6. The petitioner has claimed Normal Value in respect of exports of subject goods from subject countries on the basis of constructed cost of production by taking international price of raw material and consumption norms of Indian Industry. The Authority has, prima facie, considered the Normal Value of subject goods in subject countries on the basis of their constructed cost of production.

EXPORT PRICE

7. The petitioner has determined export price of subject goods from subject countries on the basis of analysis of import figures collected from secondary sources. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, port expenses in the country of exports, port handling and port charges to arrive at the Export Price at ex-factory level.

DUMPING MARGIN

8. There is sufficient evidence that Normal Value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the net export price indicating prima facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

INJURY AND CAUSAL LINK

9. Petitioner has furnished information on various parameters relating to material injury and threat of injury. Parameters such as

significant rate of increase of dumped imports from the subject countries, increase in market share of imports as a proportion to total demand, decrease in market share held by Indian producers, decrease in sales value and unit price, low return on investment, price undercutting and price suppression, prima facie, indicate collectively and cumulatively that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping and is also facing threat of injury.

INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

10. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

PERIOD OF INVESTIGATION

11. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st January 2002 to 31st December 2002.

SUBMISSION OF INFORMATION

12. The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi – 11 00 11.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

TIME LIMIT

13. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being

addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

14. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interest party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority